परिवर्तन

एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का झाबुआ मॉडल

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, झाबुआ (म.प्र.)

PARIVARTAN

JHABUA MODEL OF INTEGRATED WATERSHED DEVELOPMENT.

District Rural Development Agency, Jhabua (M.P.)

822 INMP95

822-INMP95-13569

आलेख एव सपादन :
डॉ. राजेश राजौरा

प्रकाशन :
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,
झाबुआ (म.प्र.)

चेतावनी :
इस प्रकाशन के किसी भी अंश का उद्धरण, पुनर्प्रकाशन अथवा पुनर्मुद्रण बिना जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, झाबुआ की अनुमति के नहीं किया जा सकता है।

संपर्क
डॉ. राजेश राजोरा, IAS
कार्यपालिक निदेशक
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत
झाबुआ, जिला झाबुआ (म.प्र.)
दूरभाष : 07392-44323
फैक्स : 07392-43611

मुद्रण
गोयनका ऑफसेट प्रिन्टर्स (प्रा.) लि. इन्दौर

Script and Editing :
Dr. Rajesh Rajora

Published by :
District Rural Development Agency,
JHABUA, Dist. Jhabua (M.P.)

No part of this publication should be copied, reproduced or printed in any form, without the prior approval/permission of District Rural Development Agency, Jhabua.

For any inquiry/details, please contact/write to :
Dr. Rajesh Rajora,
Executive Director & D.R.D.A. &
Chief Executive Officer Zila Panchayat
JHABUA (M.P.)
Phone : 07392-44323
Fax No. : 07392-43611

Printed by
Goenka Offset Printers (P) Ltd., Indore

दिग्विजय सिंह
मुख्य मंत्री

मध्यप्रदेश शासन
भोपाल ४६२००४

१४ अक्टूबर, १९९६

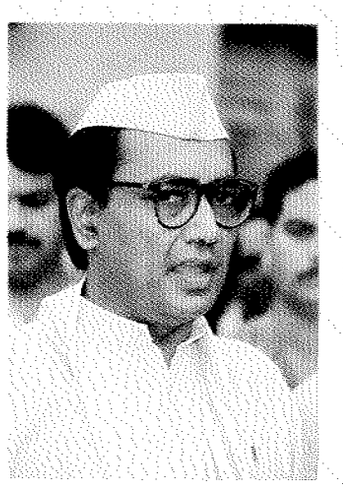

BARCODE 13552
922 INMP95

संदेश

मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि राजीव गांधी जहग्रहण प्रबंधन मिशन में झाबुआ जिले में गत दो वर्षों में अर्जित की गई उपलब्धियों की जानकारी को पुस्तिका के रूप में प्रकाशन किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा २० अगस्त, १९९४ को सात राजीव गांधी मिशन आरंभ किए गए हैं। इन मिशनों के ध्येय शासन स्तर से संचालित जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को नई दिशा देते हुए एक समय सीमा में चरणबद्ध रूप से समस्त संसाधनों का उपयोग करते हुए पूर्ण कराया जाना है। मध्यप्रदेश शासन के इन मिशनों में राजीव गांधी जलग्रहण प्रबंधन मिशन महत्वपूर्ण है। झाबुआ जिले में राजीव गांधी जलग्रहण प्रबंधन मिशन के अन्तर्गत नैसर्गिक संसाधनों का विकास एव उपयोग जलग्रहण समितियों के माध्यम से समेकित रूप से क्रियान्वित किए जाने के आशातीत परिणाम सामने आए हैं। ग्रामवासियों को संगठित एवं प्रशिक्षित कर उनके माध्यम से कार्य योजना तैयार करना, क्रियान्वित कराना तथा सामुदायिक संसाधनों का रख रखाव एवं सदुपयोग सुनिश्चित कराना प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूत करने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार की मार्गदर्शिका का अनुपालन करते हुए मिशन मोड में कार्य कर लगभग १.०० लाख हेक्टर भूमि में समेकित जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्य प्रारंभ होने से जिले के गरीब ग्रामीण भाई चहुँमुखी विकास की ओर अग्रसर हैं।

इस पुस्तिका के प्रकाशन से मध्यप्रदेश में एवं देश के अन्य जिलों में भी जलग्रहण के कार्यक्रम के प्रति प्रेरणा एवं नई सोच उत्पन्न होगी।

पुस्तिका के सफल प्रकाशन के लिए मेरी शुभकामनाएं।

(दिग्विजय सिंह)

झाबुआ जिले में राजीव गांधी जलग्रहण प्रबंधन मिशन को दिनांक २०.१०.९४ से मिशन मोड में प्रारंभ किया गया। भारत सरकार द्वारा जलग्रहण विकास संबंधी मार्गदर्शिका एवं राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप विभिन्न परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों के सहयोग से सुनिश्चित रोजगार योजना, सूखा उन्मुख क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम अन्तर्गत वाटरशेड कार्य प्रारंभ किये गये।

प्रकृति में सभी हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए है तथा मूलतः परस्पर पूरकता के संदर्भ में ही जुड़े हैं। यदि प्रकृति तथा समाज के कार्यक्रम इसी मौलिक व्यवस्था अनुकूल चलाये जाते हैं, अर्थात परस्पर पूरकता के संदर्भ में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन होता है तो सहज ही सफलता प्राप्त होती है।

अनेकानेक कारणों से झाबुआ जिले में व्यापक गरीबी एवं बेरोजगारी है। असमतल एवं व्यापक मात्रा में अनुपजाऊ भूमि, वनों का वृहद विनाश, पेयजल एवं सिंचाई की समस्या जिले की वास्तविकता रही हैं। सर्वाधिक निरक्षरता, जनसंख्या विस्फोट, अत्यधिक अपराध एवं अज्ञानता तथा अन्धविश्वास जिले का यथार्थ हैं। निरक्षरता,. अत्यधिक आबादी, अनुपजाऊ भूमि एवं सिंचाई के अभाव के कारण जिले से भारी तादाद में पलायन भी होता रहा है।

झाबुआ जिले का एक बड़ा हिस्सा ३० प्रतिशत से अधिक ढलान वाला है। भू-संरक्षण के उपयुक्त उपायों के अभाव में बेहद तीव्रता से भूमि का क्षरण होकर पहाड़ियों एवं ढलान से लाखों टन मिट्टी नदी-नालों के माध्यम से बह गई है। अनियंत्रित चराई एवं अवैध कटाई तथा अग्नि आदि की घटनाओं के कारण वनों की स्थिति निरन्तर बिगड़ती रही। लगभग एक दशक से जलसंग्रहण संवर्धन एवं उपयोग की दिशा में काफी उत्साहवर्धक पहल हुई, जिसके तहत १००० स्टापडेम ८०० तालाब एवं ११०० लघु उद्वहन सिंचाई योजनाओं का निर्माण किया गया, परन्तु समुदाय की सहभागिता से भू-सरंक्षण एवं वनों के प्रबंधन आदि की दिशा में समुचित पहल नहीं हो सकी। राजीव गांधी जलग्रहण मिशन के अन्तर्गत समाज एवं प्रकृति के परस्पर पूरकता के संबंधों पर विकास की सोच के आधार पर एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन का झाबुआ मॉडल तैयार किया गया, जिससे कि समुदाय की सक्रिय सहभागिता से नैसर्गिक संसाधनों का समुचित विकास, प्रबंधन तथा सदुपयोग हो सके।

झाबुआ जिले में जलग्रहण क्षेत्र विकास हेतु १७८ माईक्रोवाटरशेड में कुल क्षेत्रफल १,००,००० हैक्टर में जलग्रहण क्षेत्र उपचार का कार्य लिया गया है। इससे २६४ ग्राम एवं १.३३ लाख जनसंख्या लाभान्वित होगी। सर्वप्रथम १३ शासकीय एवं ६ अशासकीय संस्थाओं का चयन परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में किया गया और इनका सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ कराया गया। आस्थामूलक कार्य के रूप में ग्राम की समस्याओं का पता लगाकर विद्युत व्यवस्था, जल व्यवस्था, चौपाल निर्माण, स्कूल भवन निर्माण, देवस्थल निर्माण आदि के कार्य संपादित कराए गए। कलाजत्था, रैलियाँ, कठपुतली कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक एवं घर-घर सम्पर्क के माध्यम से समाज को जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के प्रति अभिप्रेरित किया। पीआरए/आरआरए एवं भू-साक्षरता के माध्यम से ग्रामीण जनों से सम्पर्क होने के साथ-साथ क्षेत्र के संसाधनों एवं ग्रामीणों की समस्याओं की जानकारी प्राप्त की गई। तदुपरान्त परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा उपयुक्त वाटरशेड योजना के सही क्रियान्यवन से होने वाले संभावित लाभों के बारें में ग्रामीणों से विस्तृत परामर्श किया गया। प्रत्येक माइक्रोवाटरशेड के जागरूक ग्रामीण महिला एवं पुरुषों को रालेगाँव शिन्दी तथा उरुलीकंचन सफल जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यो के अवलोकन हेतु भ्रमण आयोजित किये गये। उपयुक्त स्वयं सेवी समूहों एवं उपभोक्ता समूहों के गठन की कार्यवाही संपादित की गई ताकि अधिकाधिक ग्रामीणों की वाटरशेड विकास के कार्यों में सक्रिय एवं प्रभावी सहभागिता हो। तत्पश्चात् पंचायत प्रतिनिधियों एवं विभिन्न उपभोक्ता एवं स्वयंसेवी समूहों से वाटरशेड कमेटी के सदस्यों का चयन किया गया। परियोजना क्रियान्वयन दल के सदस्यों के तकनीकी मार्गदर्शन में उपभोक्ता समूहों के प्रस्ताव अनुरूप माइक्रोवाटरशेड की कार्य योजना तैयार की गई।

माईक्रोवाटरशेड के उपरी भाग में सतत एवं स्टेगर्ड कंटूर ट्रेंच, पत्थर के कंटूर बंड्स, गली प्लग, बोल्डर चेक, घास एवं चारागाह विकास के माध्यम से उपचार कराया गया। माईक्रोवाटशेड के बीच के भाग में गली ट्रीटमेंट, नाला बंधान, गेबियन संरचना, डाईक, परकुलेशन टेंक एवं वृक्षारोपण के माध्यम से उपचार कराया गया तथा निचले हिस्से में नाला बंधान परकूलेशन टेंक, वृक्षारोपण, हेजट्रीटमेंट, कृषि वानिकी, उद्यानिकी आदि कार्य लिए गए। भूजल संरक्षण के कार्यों से मिट्टी का कटाव एवं बहाव रोकने में मदद मिली तथा जल संरक्षण कार्यो से जल स्तर एवं डिस्चार्ज में सुधार हुआ तथा नालों में प्रवाह की स्थिति निर्मित हुई। चारागाह एवं वानस्पतिक पुनरोत्पादन एवं वृक्षारोपण के क्षेत्रों की सुरक्षा एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी उपभोक्ता समूहों जिनमें ग्रामवन समितियाँ भी शामिल है, के द्वारा सफलतापूर्वक वहन की गई। वाटरशेड एवं संयुक्त वन प्रबंधन के अभियानों से परस्पर वनों की सुरक्षा एवं पुनरोत्पादन तथा प्रबंधन के प्रति उचित माहौल निर्मित हुआ। बीजों के माध्यम से रतनजोत नीम, प्रोसोपेस, खैर, सफेद खेर आदि प्रजातियों का अत्यन्त सफल अंकुरण कराया गया। जिले में दीनानाथ, स्टायलो हमेटा, सुकली भतौड़ी आदि घासों का वृहद उत्पादन किया जा रहा है, जिसकी वजह से इस वर्ष झाबुआ जिला प्रथम बार चारे की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो जाएगा। जिले में बांस, आंवला, नीम, सीवन, खैर, बैर आदि के वृक्षों के रोपण को प्राथमिकता दी गई है। जिले में मुख्यतः ऐसी प्रजातियाँ चुनी गई है जो कि क्षेत्र की प्राकृतिक जलवायु के अनुरूप हो तथा जिनके उत्पादन से ग्रामीणों की जरुरतों की पूर्ति होने के अतिरिक्त ग्रामोद्योग की दृष्टि से भी उपयोग हो तथा आमदनी एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायक हो। इस दृष्टि से बांस, आंवला, एवं रतनजोत को इस वर्ष सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। विभिन्न घासों का लगभग १५.०० लाख क्विंटल उत्पादन संभावित है तथा बीज बुवाई से रतनजोत के लगभग १.०० करोड़ पौधे उत्पन्न हुए हैं। अगले वर्ष बांस के १५ लाख एवं आंवले के १० लाख पौधे लगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है।

महिलाओं में बचत, संगठन, उद्यमिता तथा आत्म विश्वास का विकास करने तथा साहुकार से उच्च दर के कर्ज से मुक्त करने की दृष्टि से ''बयरानी कुलड़ी'' उर्फ ''महिला बैंक'' की स्थापना की गई। इस बैंक की मालिक तथा मैनेजर ये महिलायें ही है और अधिकाशतः उपभोक्ता भी यही महिलायें हैं। ये स्वयं ऋण की मात्रा, ब्याज की दर तथा भुगतान की समयावधि तय करती है। कुछ समय पश्चात् ये महिला समूह ग्रामोद्योग जैसे आर्थिक उत्पादन की गतिविधियों में भी शामिल होगी। जिले में वर्तमान में जलग्रहण क्षेत्रों में ३५६ बयरानी कुलड़ी कार्यरत हैं।

कल्पतरु योजना के माध्यम से गरीब कृषकों के निजी खेतों में शुष्क उद्यानिकी का विकास किया जा रहा है। दो लाख बेर के देशी प्रजाति की झाड़ियों में बडिंग का कार्य कर उन्नत किस्म में परिवर्तित किया गया है। कृषि वानिकी का विकास किया गया है। ईंधन की बचत हेतु धुँआ रहित चूल्हे, सोलर कूकर एवं बायोगैस संयंत्रों के विस्तार का कार्य किया गया है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लोक व्यापीकरण हेतु वाटरशेड कमेटी के सक्रिय सहयोग से पोरियावाड़ी, फलिया स्कूल एवं साक्षरता कक्षायें संचालित की जा रही हैं। भू-जल संरक्षण के कार्यों से उपलब्ध नैसर्गिक संसाधन जैसे - जल, अच्छी मिट्टी, चारा, रतनजोत एवं बाँस तथा आंवला आदि उत्पादनों के सदुपयोग की कार्यवाही भी प्रारंभ की गई है, जिसके तहत कुओं, नालों, स्टापडेम एवं तालाबों से उद्वहन सिंचाई योजना, मत्स्य पालन, डेयरी उत्पादन, ग्रामोद्योग तथा उद्यानिकी के विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ग्रामीणों में जागृत चेतना तथा अपने संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन में निभाई जा रही सक्रिय सहभागिता से विकास की नई अवधारणा निर्मित हुई है तथा लोकतंत्र की जड़े मजबूत हुई हैं। गांधीजी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार होने की छोटी सी किरण भी दिखाई देने लगी है।

मनोज झालानी
कलेक्टर एवं मिशन लीडर
राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबन्ध मिशन, झाबुआ (म.प्र.)

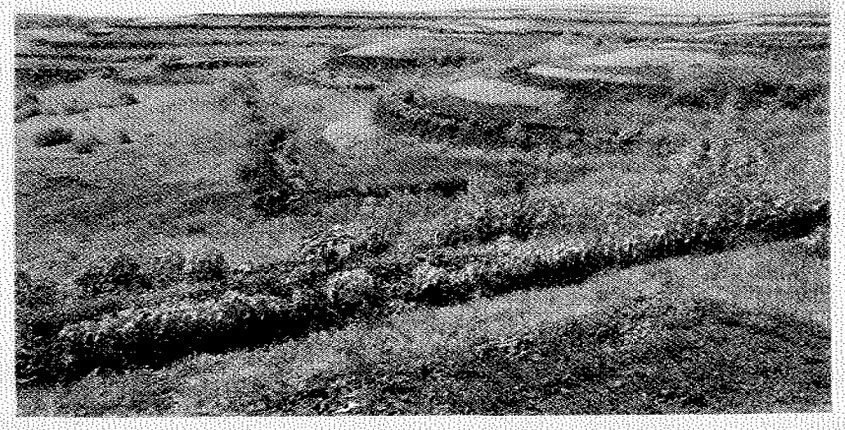

Rajiv Gandhi Watershed Management Mission was started on mission mode in Jhabua district from 20-10-94. Watershed work was initiated under Employment Assurance Scheme, Drought Prone Area Programme and Integrated Wasteland Development Programme by appointing project implementing agencies and following instructions given by the Government of India and Government of Madhya Pradesh.

Everything in nature is linked with everything else and are mutually complementary. Only those Programmes would succeed, which can cater to the relationship operating between nature & the mankind.

Jhabua district is full of rampant poverty and unemployment. Undulating terrain and undeveloped lands on large scale, destruction of huge areas of forests, problems of drinking water and irrigation are the stark realities of the district. Extensive illiteracy, Population explosion, enormous crimes and ignorance and superstitions are predominent. The district has also been known for excessive migration due to illiteracy population explosion, undeveloped lands and lack of facilities of irrigation.

Most of the areas of Jhabua district has a gradient of more than 30 percent. Due to lack of proper methods of soil conservation. soil erosion has taken place at a very high pace and millions of tonnes of soil has been washed away from hills and hillocks and undulating terrain. Incidents of uncontrolled grazing, illegal felling and fires etc. have continuously degraded forests, In last one decade promising initiative had been taken up in water harvesting and water collecting techniques, Around 1000 stopdams, 800 tanks and 1100 community lift irrigation schemes have been constructed but soil and water conservation works with community participation and joint forestry management was lacking. In Rajiv Gandhi Mission on Watershed Development, development was tried keeping in view the need of mutual synergy and interdependence in various forces of community and nature. This has resulted into Jhabua Model of Integrated Watershed Development for active community participation in Multifaced Development, management and utilisation of all community and personal natural resources.178 microwatersheds with a total area of around 1,00,000 hects. was taken up for watershed treatment under Watershed Devlopment Programme.in Jhabua. This would benefit a population of 1.33 lakhs spread over 264 villages. Initially 13 governmental and 6 nongovernmental organisations selected as project implementing agencies and intensive training programme was started. Further tracing the fundamental problems of the villagers, entry point activities like electricity, drinking water, Chopal, School building etc. were taken up. To organise the community and creating awareness for watershed development, a strategy involving Kala Jattha, rallies, puppetshows, streetplays and house-to-house contact was adopted and was implemented with vigour. With the help of PRA and RRA and land literacy a live contact was maintained with the individual and the community and identification of problems of villagers and the resources in the area could be done. Further, exhaustive and detailed communication between the Villagers and project implementing agencies was initiated for discussions on strengths, weaknesses, opportunities and threats of possible benefits from porper implementation of watershed plan. Enlightened and active rural women and manfolk from every watershed area were taken to Ralegaon Shinde (Maharashtra) and Urulikanchan on exposure visits. Proper self-help groups and user groups were identified and organised so that most of the villagers could actively and effectively participate in watershed development works. Similarly water shed development committee members were selected from Panchayat representatives and various self-help and user groups. Action plans of micro watersheds were prepared by the Project Implementation Agencies with the help of proposals from various user groups.

Upper zones of micro watershed were treated with continuous and staggared contour trenches, boulder contour bunds, Gully plugs, boulder checks, fodder and grassland development. Transition zones of microwatershed were treated with gully treatment, nallah checks, Gabionic structures, dykes, percolation tanks and plantations. Discharge zone of microwatersheds was treated with nallah checks, percolation tanks, plantations, hedge treatment, agro-forestry, horticulture etc. Soil erosion and run-off of water could be effectively checked and stopped by soil conservation methods, and water harvesting structures have resulted in improvements in water-tables and water discharge and perennial streams could be generated. Fodder development and vegetative regeneration and mangement was successfully taken care of by various user groups, this included village forest commitees. Watershed and joint forestry management campaigns created posititive atmosphere and environment for protection, regeneration and management of degraded forests. Successful germination from seeds could be achieved in various species of Ratanjot (Jatropa), Neem, Prosopis, Kher, White Kher etc. Extensive production of Deenanath, Stylohemata, Sukli, Batodi etc. grasses have created a situation where Jhabua district could be self-sufficient in fodder from this year for the first time. Priority has been accorded to plantations of bamboo, Amla, Neem, Kher, Sewar, Ber etc. Fundamentally emphasis has been given to species which are a suitable to the weather conditions prevailing in this eco-climatic zone, could fulfill the demands and aspirations of villagers, could be useful for development of village industries and could generate employment and means of llivelihood. Hence special priority is given to bamboo, Amla and Ratanjot (Jatropa) this year. Approximately 1.5 million quintals production of various grasses is expected this year and approximately 10 million Ratanjot (jatropa) plants have been germinated from seeds sowing. Preparation for plantations of 1.5 million bamboo trees and 1 million Amla trees have been ensured for this year, to inculcate household savings, empowerment, development of self-confidence and entreprenuership in the womenfolk and to free tribal society from high interest rates of loans taken from money lenders.

'Baira-NI-Kuldi' (women banks) were established. Women are the owners and managers of these banks and mostly they are the users as well. They decide the quantum of loan, interest rates and repayment durations. Later on these women groups are envisaged to take up economy generating activities like village industries etc. Presently, there are 356 such 'Baira ni Kuldis' operating in watershed areas of the district.

Dryland horticulture has been developed on private land/farms of below povertyline villagers with the help of "Kalptaru" scheme. 2 lakhs indegenous trees of Ber have been converted by budding and grafting methods into high yielding variety. Similarly agro-forestry has been promoted. Fuelwood saving devises like smokkeless chullahs Sigris solar cooker and biogas plants extension and propogation has also been taken up. For universalisation of education and health, Poriawadi, Falia-schools and literacy classes are run and managed by active participation of watershed development committees. Proper and effective utilisation of natural resourses like water, productive soil, fodder, Ratanjot (Jatropa), bamboo and Amla, etc. by integrated water and soil conservation techniques has been initiated, Lift irrigation schemes on wells, streams, rivers, riverlets, stopdams and tanks have been promoted and fisheries, dairy, village industries and horticulture activities dovelopment has also been emphasised. Awareness created in the villagers and active participation in the field of development and management of resources has resulted in the new philosophy for restrengthening of roots of democracy. Similarly, Gandhiji's dream of "Gram-swaraj" has to an extent also taken shape in the remote corners of Jhabua district.

Manoj Jhalani
Collector & Mission Leader
Rajiv Gandhi Mission Water Shade Development Jhabua (M.P.)

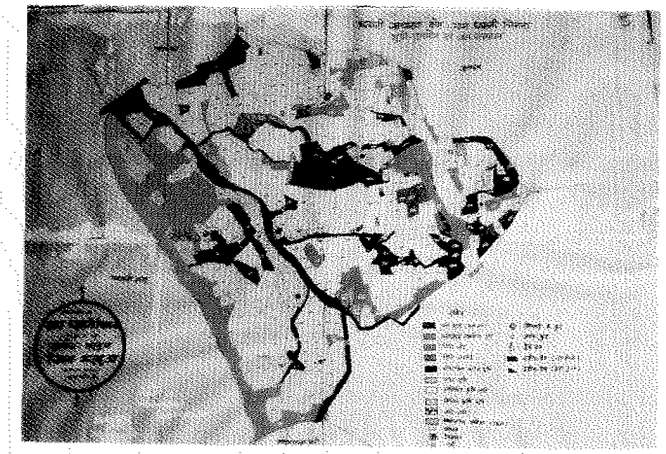

सुदूर संवेदन तकनीक का प्रयोग

सर्वप्रथम सुदूर संवेदन तकनीक के नक्शों से जलग्रहण क्षेत्रों को चिन्हित कराया गया एवं भू-जल स्तर, जिओमोर्फोलोजी, भूमि का ढलान दर्शाने वाले नक्शे, भूमि उपयोग के नक्शे एवं जलप्रवाह के नक्शे तैयार कराये गये, जिनका उपयोग परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्य योजना तैयारी में किया गया।

Using Remote Sensing Technique

Initially, demarcation of watershed areas on maps was done using remote sensing techniques and detailed maps of ground water levels, geomorphology, slope, land use and water drainage were prepared which were used by project implementation agencies in preparation of the action plans.

लोगों की बात – लोगों के साथ

जलग्रहण क्षेत्र में रैलियों, कलाजत्थी, समग्र विकास रथ, नुक्कड़-नाटक, कठपुतली कार्यक्रम तथा घर-घर संपर्क से भू-जल संरक्षण, वन संरक्षण एवं संसाधनों के प्रबंधन में ग्रामीणों की सहभागिता के प्रति जागरूकता विकसित की गयी एवं जलग्रहण कार्यक्रम के प्रति अभिप्रेरित किया गया। परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों के तकनीकी मार्गदर्शन में वाटरशेड कमेटियों द्वारा कार्य योजना तैयार की गयी।

With the people-for the people.

Awareness was created and participation was ensured for water and soil conservation, forestry management and resource management in the watershed development areas by organising rallies, Kalajatthas, integrated development Raths, Street plays, puppet shows, house-to-house contact, etc. Watershed development committees prepared action plans under technical guidance of Project Implamentation Agencies.

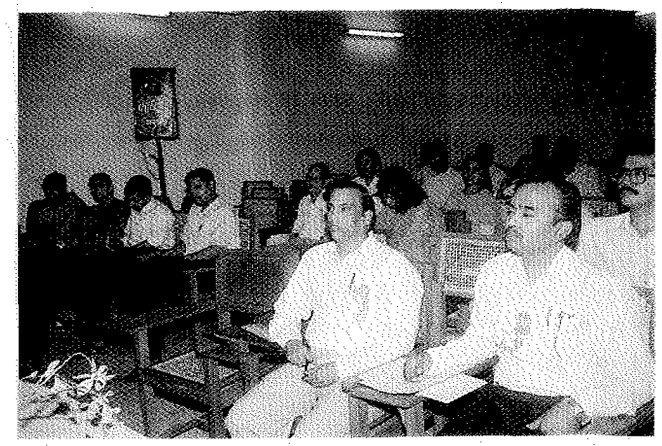

प्रशिक्षण – सफलता की कुंजी

परियोजना अधिकारियों, परियोजना क्रियान्वयन दल के सदस्यों, सामाजिक संगठकों, स्वयंसेवकों, वाटर शेड कम्मेटी के सदस्यों तथा ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया गया। भूमि के हर टुकड़े पर जाकर भू-साक्षरता अभियान संपादित कराया गया। जिले में तथा जिले के बाहर कुल २३ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा चुके हैं।

Training : Key to success

Project officers, Project Implementing Agency members, project coordinators, community organisers, volunteers, water shed development committee members and villagers were imparted training in various aspects of integrated watershed development. Land literacy campaign was organised on each and every land/farm plot in the villages. In all so far, 23 intensive and extensive training modules have been organised in and outside the district.

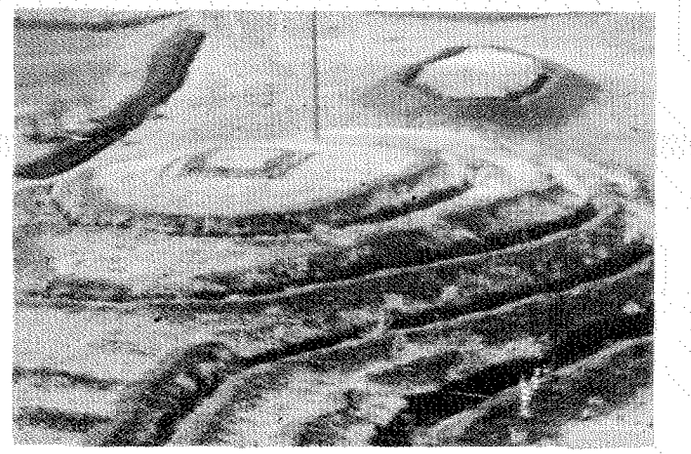

अपर रिज ट्रीटमेंट

जिले में वर्तमान में संचालित समस्त १३८ माईक्रो वाटरशेड में वर्ष १९९४-९५ एवं १९९५-९६ में अपर रिज ट्रीटमेंट पूर्ण कराया गया है। इसमें स्टेगर्ड एवं कंटीन्यूअस कंटूर ट्रेंच, कन्टूर बोल्डर वॉल, गलीप्लग्स, गली ट्रीटमेंट, नालाबंधान, वानस्पतिक आच्छादन एवं चारागाह विकास को प्राथमिकता दी गयी।

Upper ridge treatment

Presently in the district, upper ridge treatment has been completed in all 138 micro watersheds in the year 1994-95 and 1995-96. Primarily staggered and continuous contour trenches, contour boulder walls, gully-plugs, gully treatment, nalla checks, vegetative cover and fodder development activities have been emphasised.

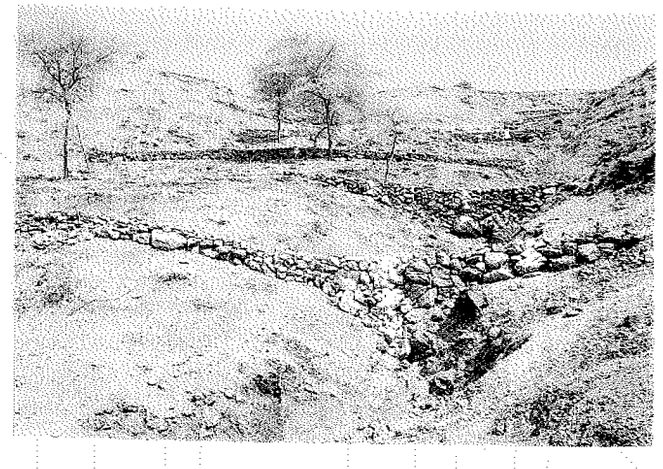

ट्रांजीशन जोन ट्रीटमेंट

ट्रांजीशन जोन में नालाबंधान, बोल्डर बंधान, वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास के साथ ही गेबियन संरचना, डाइक्स आदि का निर्माण कार्य कराया गया है। ट्रांजीशन जोन के अंतर्गत निजी खेतों में मेढ़ पर बंधान एवं कृषि की जल तथा भूमि कटाव को रोकने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया गया।

Transition Zone Treatment

In the transition zone, apart from plantations and fodder development - nalla bunds, boulder checks, Gabionic structures and dykes have been constructed. In the transition zone field bunds on private farmlands and the use of soil and water conserving techniques in agriculture have been encouraged.

लोअर जोन ट्रीटमेंट

जिले में संपादित माईक्रो वाटरशेड के सबसे निचले हिस्सों में कृषि के विकास को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है। नालों पर मिट्टी तथा बोल्डर के बंधान, परकोलेशन टेंक, संकन पौण्ड, फार्म पौण्ड का भी सफलतापूर्वक निर्माण कराया जा रहा है। लोअर रिजेस में स्थित छोटे-छोटे निस्तारी तालाब एवं सिंचाई तालाबों के सुदृढ़ीकरण की व्यवस्था की गयी है। सिल्वीपाश्चर, कृषिवानिकी एवं शुष्क उद्यानिकी को भी बढ़ावा दिया गया।

Lower Zone Treatment

A lot of emphasis on development of agriculture and allied activities has been laid in lower reaches of micro watersheds. Earthen and boulder nalla bunds, percolation tanks, sunken ponds and farm ponds have also been successfully constructed. Similarly re-structuring and re-strengthening of small Nistari and irrigation tanks have also been ensured in the discharge zones. Silvi-pasture, agro-forestry and dryland horticulture have also been promoted.

चारा विकास

जिले में क्रियान्वित माईक्रो वाटरशेड में अपर ट्रांजीशन एवं लोअर जोन्स में निजी तथा शासकीय (वन अथवा राजस्व) भूमि पर चारे के विकास का कार्यक्रम वृहद पैमाने पर लिया गया। जिले में मुख्यत: दीनानाथ, सुखली, भतोड़ी एवं स्टायलोहेमटा घास को उगाया गया। विगत एक वर्ष में जलग्रहण क्षेत्रों से लगभग ५.०० करोड़ रुपये कीमत के चार करोड़ पुले (लगभग ५ लाख क्विंटल घांस) का उत्पादन किया गया। ऐसे लाभ से ग्रामीणजन जलग्रहण कार्यक्रमों से सहजता से जुड़े हैं।

Fodder Development

Exhaustive programme for fodder development on upper transition and lower transition zones in private and government (Forest/Revenue) land has been taken up on a large scale in the micro watersheds in the district. Mainly, Deenanath, Sukhali, Bhatodi and Stylohemeta grasses are produced in the district. Approximately 4 crore bales (roughly 5 lakh quintals) of grasses worth Rs. 5.00 crores have been harvested in watershed areas in last one year. Such benefit s have facilitated villagers to join in watershed development programme.

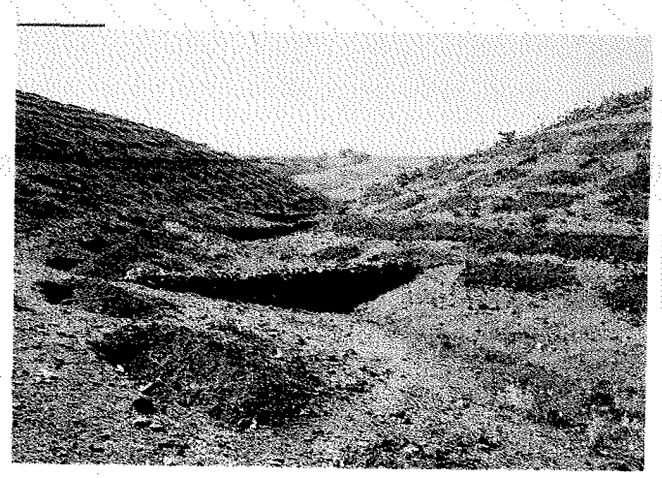

वृक्षारोपण कार्यक्रम

जिले में जलाऊ एवं ईमारती लकड़ी के वृक्ष, फलदार वृक्ष एवं बहुउपयोगी वृक्षों के रोपण का कार्य वृहद् पैमाने पर लिया गया। जिसे अगले दो वर्षो में और अधिक गति दिये जाने की पूर्ण तैयारी है।

जिले में मुख्यत: बीज अंकुरण से रतनजोत (जेट्रोपा) खेर, सुबबूल, प्रोसोपिस के लगभग २ करोड़ पौधों का अंकुरण किया गया है। इसके साथ ही ५.६२ लाख बांस का रोपण भी किया गया है। आंवला के लगभग १५ लाख पौधों का वृक्षारोपण अगले तीन वर्षो में किया जाना प्रस्तावित है। जिले में आम, नीम, सीवन, युकेलिप्ट्स, सीताफल, बैर, साजा के अत्यधिक उत्साहवृर्द्धक परिणाम सामने आये हैं।

Plantation Activities

Large scale plantation of fuel and timberwood trees, fruit bearing trees and multi-purpose trees have been taken up in the district. Preparation for giving further momentum to plantation activities in the next two years is being ensured. About 2 crores of plants mainly Ratanjot (Jatropha) Kher, Subabul and prosopis have been raised through seed sowing in the areas. Along with it 5.62 lakhs of bamboos have been planted. It is proposed to take up plantations of roughly 15 lakhs Amla saplings in next three years. Mango, neem, sewan, eucalyptus, custard-apple, Ber, Saja plantations have shown extremely encouraging results in the district.

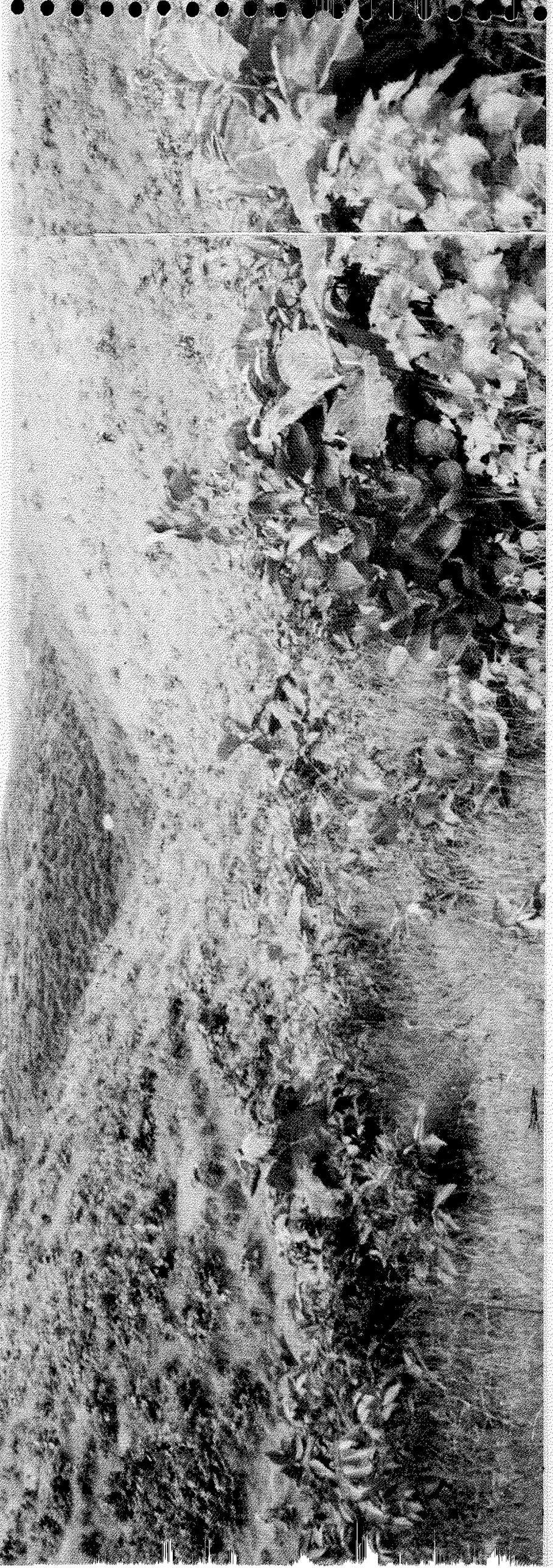

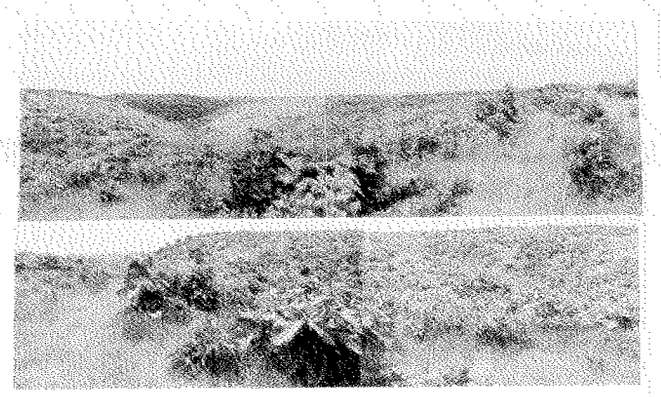

वनों का पुनर्जीवन

जिले में लगभग तीन दशक पूर्व तक घने जंगल थे जो कि बुरी तरह नष्ट हो गये। ग्राम वन समितियों तथा वाटरशेड विकास समितियों के द्वारा इन बिगड़े हुए वनक्षेत्रों की सुरक्षा एवं प्रबंधन किये जाने से वाटरशेड क्षेत्रों में लगभग १२,८०० हेक्टर के वनों का पुनर्जीवन सम्भव हुआ है। इन वनों के उत्पाद, यथा जलाऊ लकड़ी, इमारती लकड़ी, फल, बीज, घांस एवं अन्य वनोपज हेतु ग्रामीण जनों को अधिकार सौंपे गये हैं।

Natural Regeneration of Forests :

Three decades ago the district was covered with dense forests which with the passage of time were destroyed. Due to protection, management and assisted natural regeneration of these degraded forests in watershed areas by village forest committees and watershed development committees, natural regeneration of 12,800 hect. of forests has been made possible. Villagers have been given rights over forest produce like fuelwood, small timber, fruits, seeds, grasses and other non-wood forest produce.

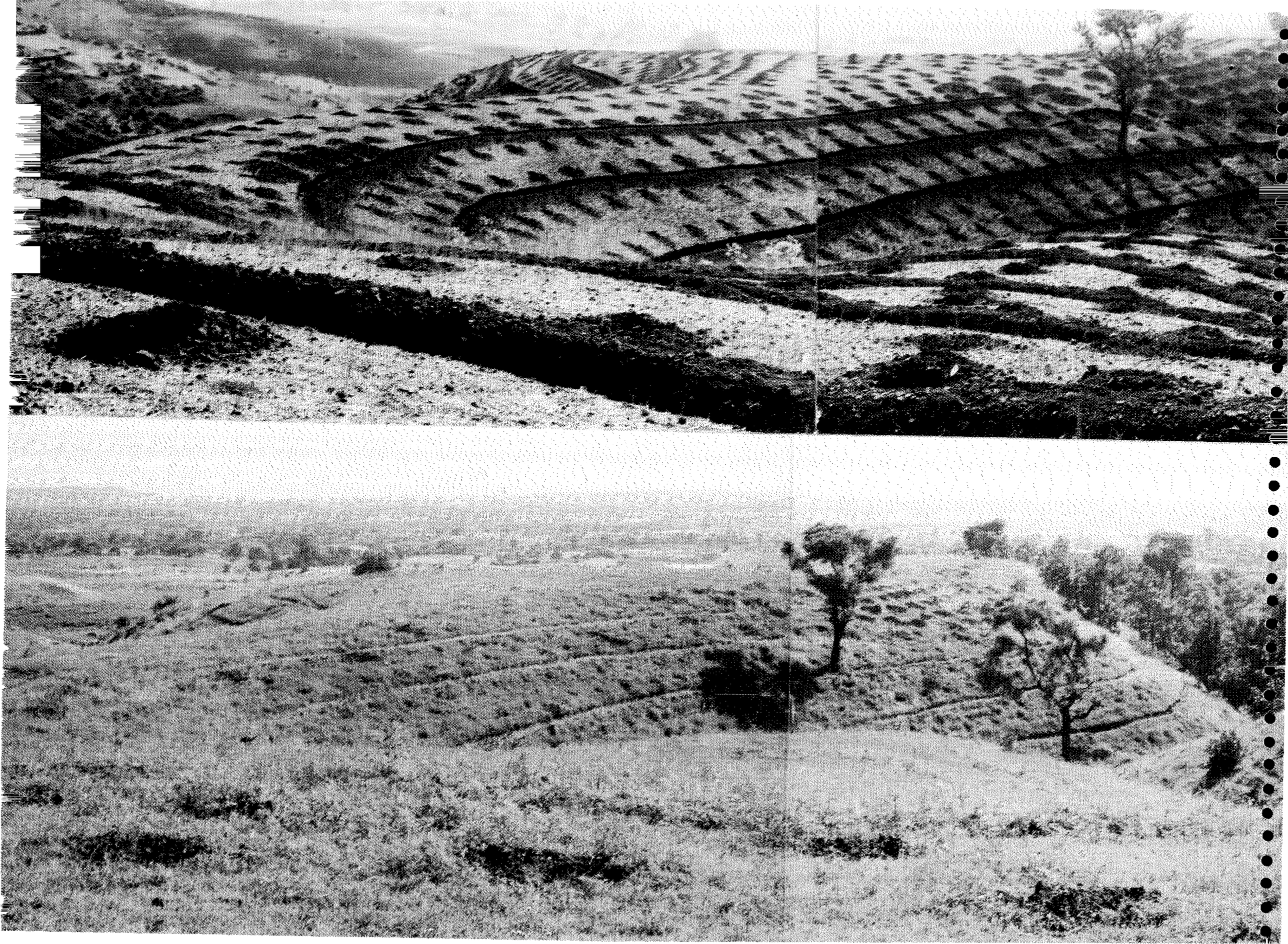

❑ माइक्रोवाटर शेड - पिपलीपाडा
विकास खण्ड - झाबुआ

❑ MICROWATER SHED - PIPLIPADA
BLOCK - JHABUA

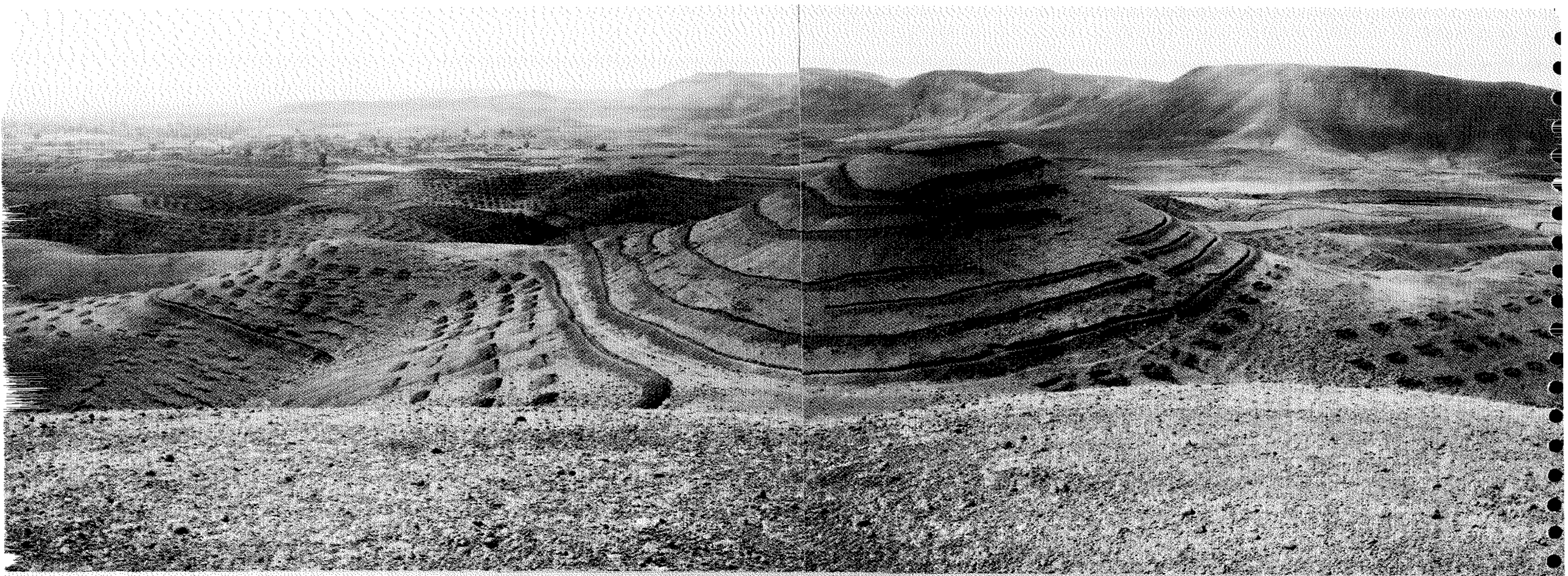

- माइक्रोवाटर शेड - मोरझिरी
  क्षेत्रफल - 362.10 हेक्टर
  विकास खण्ड - थांदला

- MICROWATER SHED - MORJHIRI
  AREA - 362.10 Hec.
  BLOCK - THANDLA

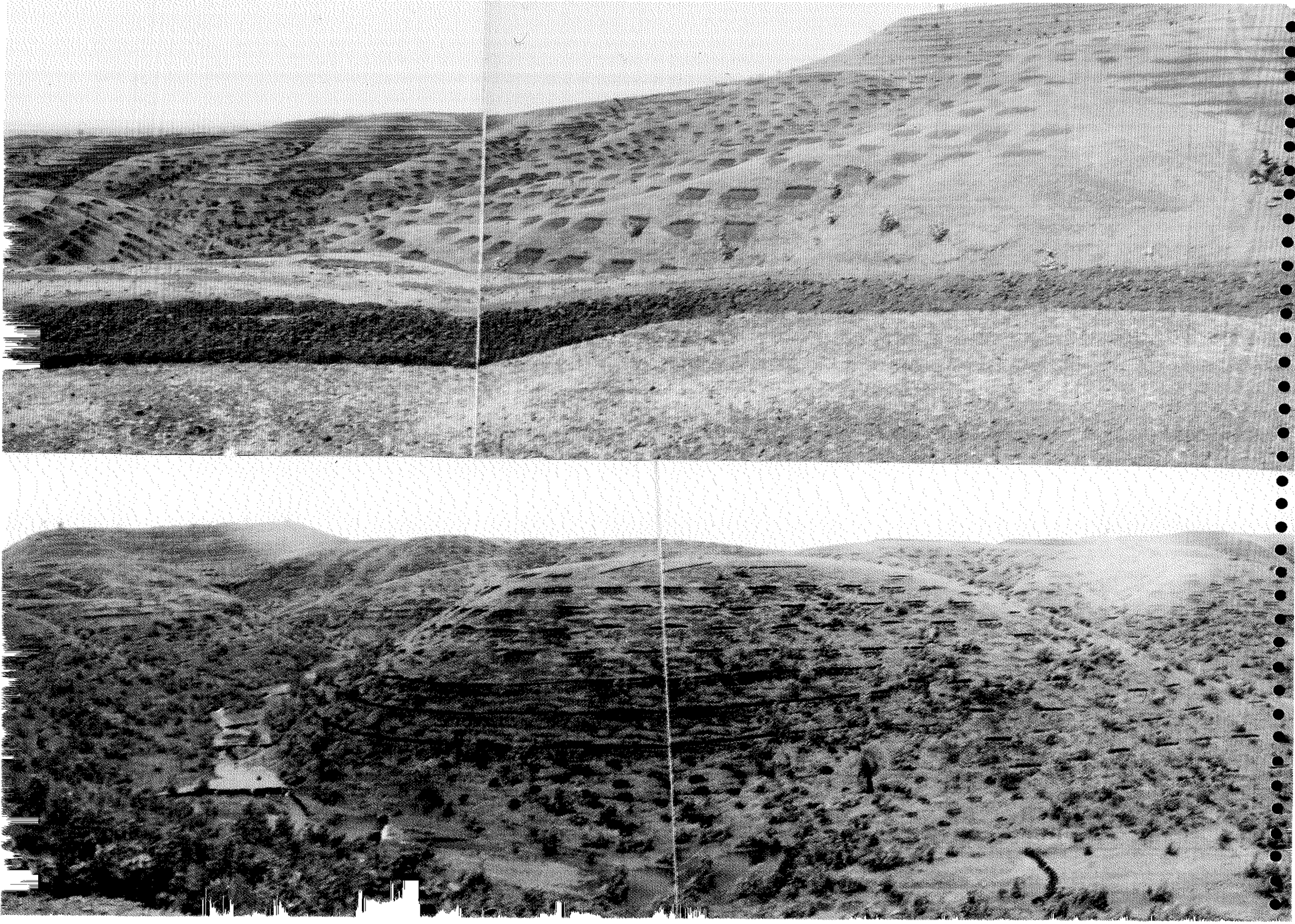

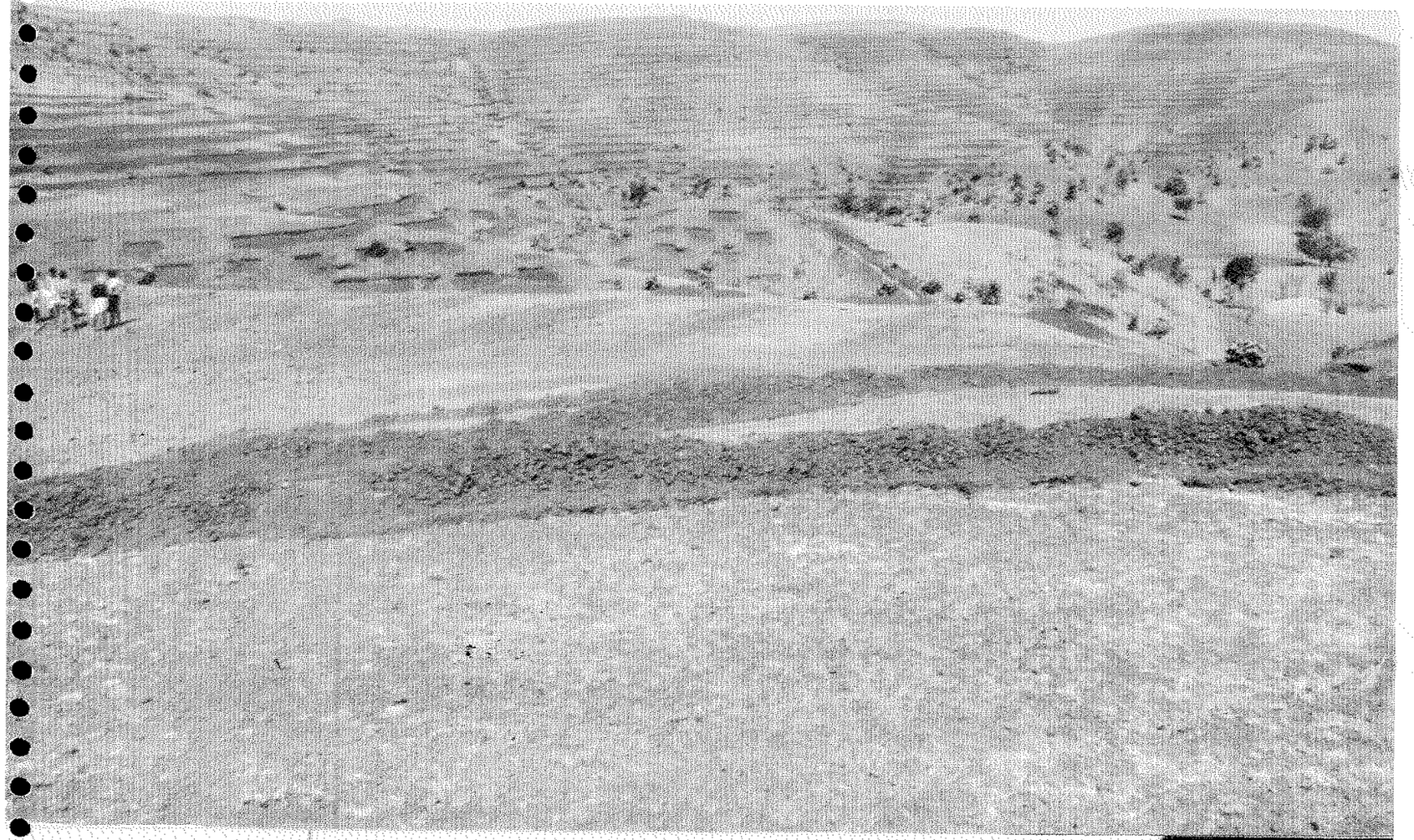

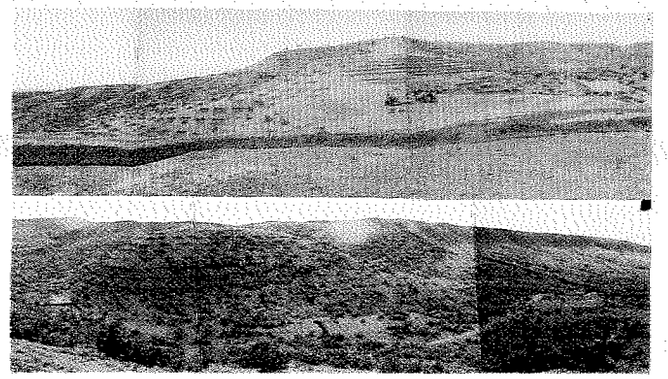

- माइक्रोवाटर शेड - हाथीपावा
  क्षेत्रफल - 173.66 हेक्टर
  विकास खण्ड - झाबुआ

- MICROWATER SHED - HATIPAWA
  AREA - 173.66 HEC.
  BLOCK - JHABUA

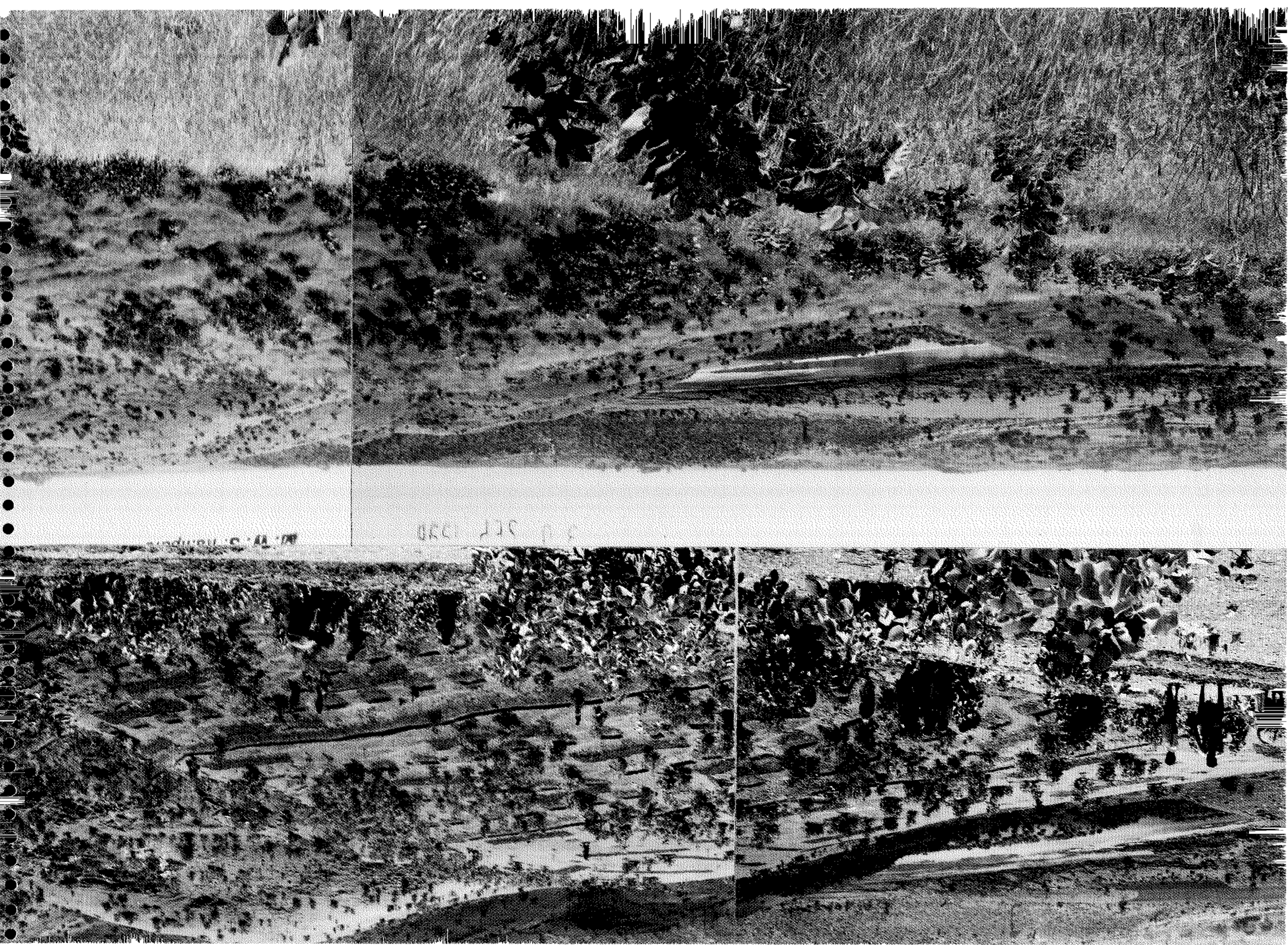

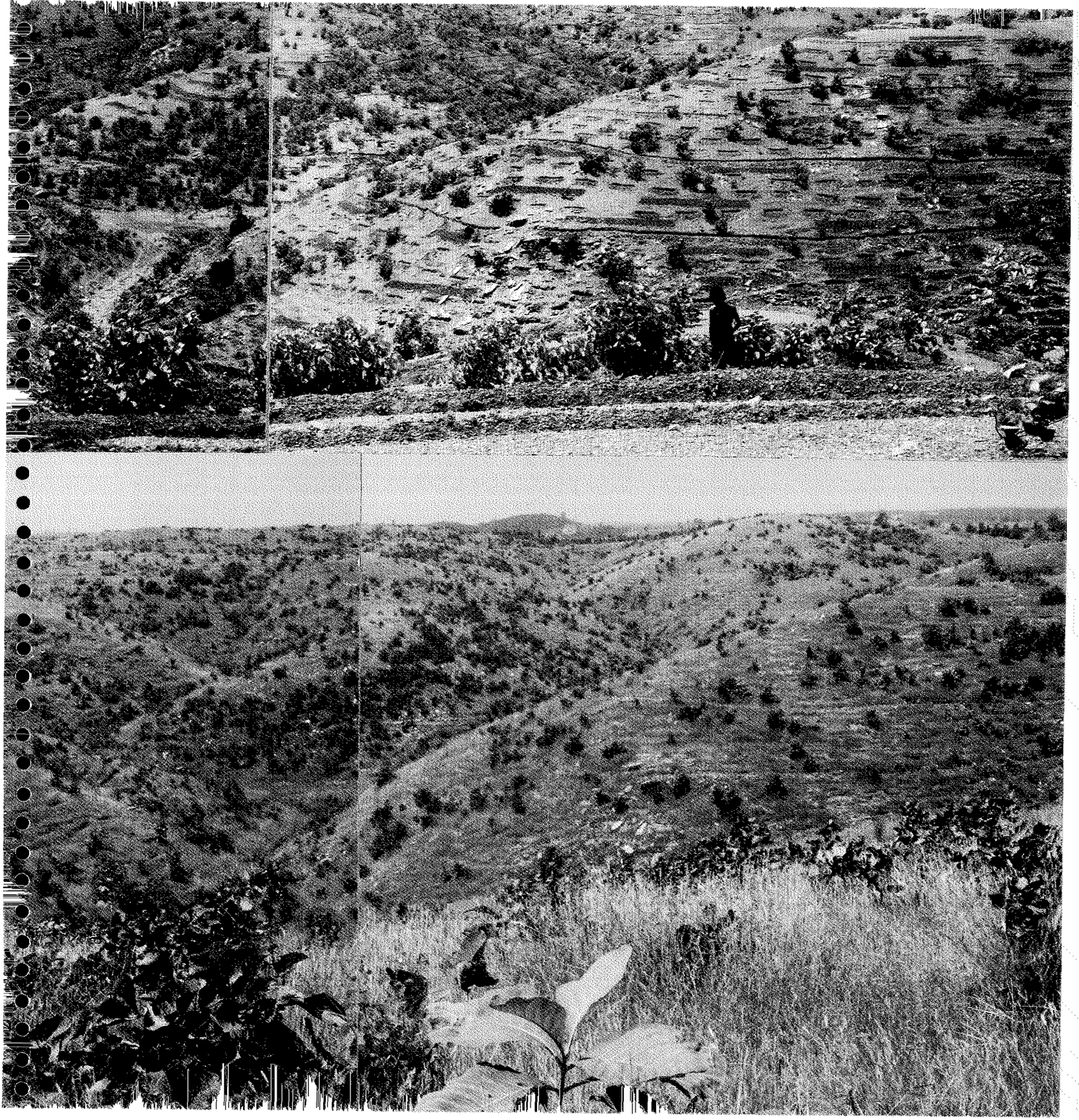

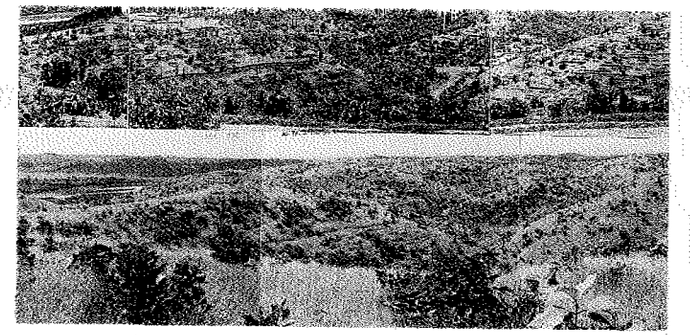

- माइक्रोवाटर शेड - रामपूरा
  विकास खण्ड - मेघनगर

- MICROWATER SHED - RAMPURA
  BLOCK - MEGHNAGER

पौधरोपणियों का विकास

जिले में जलग्रहण क्षेत्र के समस्त फलदार वृक्ष एवं बहुउपयोगी वृक्षों की प्रजातियाँ ग्राम की महिलाओं द्वारा स्वयं सहायता दलों के रूप में विकसित पौधरोपणी (नर्सरी) अथवा अपनी आंगनवाड़ी के माध्यम से विकसित कर उपलब्ध करायी जाती हैं। जिले में पिछले वर्ष स्वयं सहायता समूह की ८२ नर्सरी क्रियाशील थीं। इस वर्ष इसमें कई गुना वृद्धि की जा रही है। महिलाओं द्वारा पौधरोपण से ज्यादा बेहतर स्तर के पौधे जलसंग्रहण क्षेत्रों को उपलब्ध हो रहे हैं।

Raising Nurseries

Women self-help groups have raised saplings of fruit bearing and multipurpose trees in nurseries and kitchen gardens in watershed areas of the district. Last year there were 82 such women self-help groups nurseries in existence. There will be a manifold increase in the number of such nurseries this year. These women are instrumental in providing better quality saplings in the watershed areas.

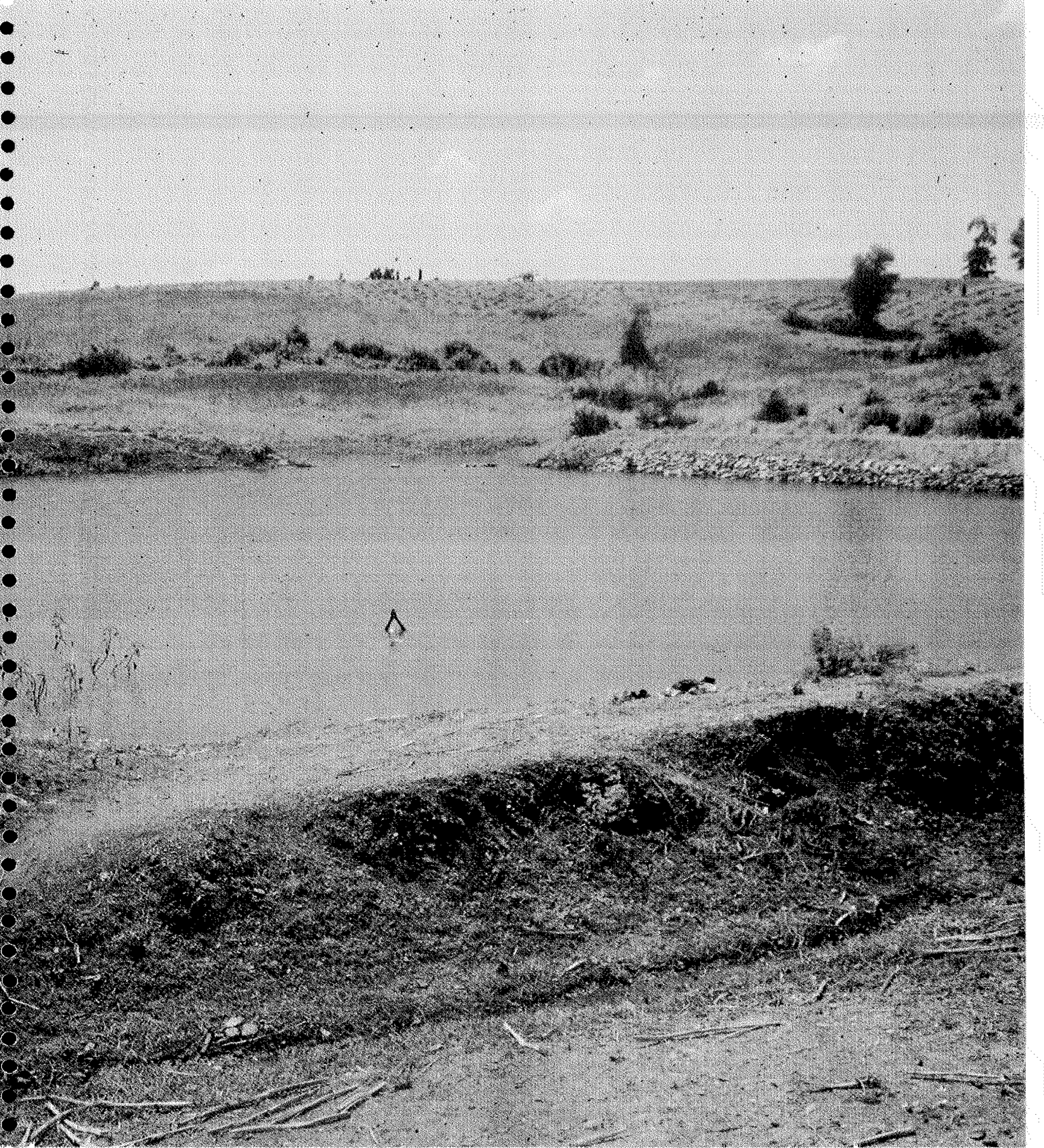

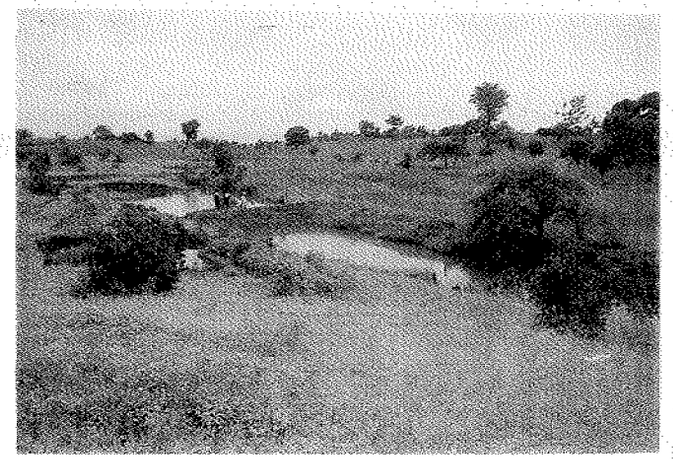

गांव का पानी गांव में–खेत की मिट्टी खेत में

जिले में जलग्रहण क्षेत्र की भूमि तथा जलसंरक्षण एवं वानस्पतिक आच्छादन से ढलानों पर वर्षा के पानी के तेज बहाव को छोटे-छोटे संरचनाओं के माध्यम से रोक कर गांव में ही पानी की हर बूंद का संचय आरंभ हो गया है। जिले में भू-जल स्तर में बढ़ौत्री हुई है और ऐसे गांव जहां कुओं, तालाब और हेण्डपंप ग्रीष्म ऋतु में पूर्व में ही सूख जाया करते थे वहां ग्रीष्म कालीन अवधि में भी पानी उपलब्ध रहता है। इसी प्रकार मिट्टी को खेत में ही रोकने के कार्य में उपचार में महती उपलब्धि हासिल हुई है।

In - situ Soil and Moisture conservation :

With the help of soil conservation works and vegetative cover in the watershed areas, fast run-off of rain water has been stopped by small structures Process of conserving every single drop in the villages of the district has started.This has resulated in increaes in agricultural area and those wells, tanks and handpumps, which used to dry up during the summers, have been converted into pereinniel sources of water. The conservation of soil in the farms has resulted in better productivity of crops.

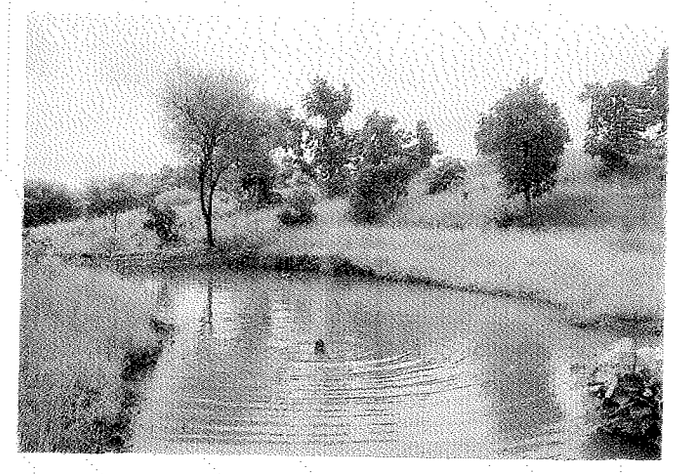

सूखे अंचल में जल ही जल

सूखा उन्मुख क्षेत्र झाबुआ जलग्रहण के उपचार कार्यों की बदौलत आज ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां पेयजल के लिए ही नहीं वरन् निस्तार, मत्स्य पालन एवं सिंचाई के लिए पर्याप्त जल का स्त्रोत पूरे वर्ष जलग्रहण ग्रामों में उपलब्ध होने लगा है। परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कुओं तथा हेण्डपंप में भू-जल स्तर का आंकलन प्रतिमाह किया जा रहा है। सूखे कुओं और सूखे हैण्डपंपों में पानी ने ग्रामीणजनों के चेहरों पर नई मुस्कान ला दी है। नालों एवं नदियों पर पूर्व में निर्मित स्टापडेम एवं वर्तमान में बनाए गये नालाबंधानों से जल रोक कर सामुदायिक उद्वहन सिंचाई योजनाएं भी क्रियान्वित की जा रही है।

Oasis

Watershed development in this drought prone area district has created a situation where besides drinking water substantial amount of water for Nistar, fisheries and irrigation is also available throughout the year in the watershed villages. Project Implementing Agencies keep a monthly record of ground water level in wells and handpumps. Water in dried wells and hand pumps has given a new meaning to lives of the villagers. Community lift irrigation schemes have been implemented on previously constructed stopdams and recently constructed nalla checks on rivers and rivuletes.

हरितक्रान्ति

जिले में कृषकों को कृषि के नये तरीके अपनाने के लिए जलग्रहण अभियान की अभिप्रेरणा एवं जागरूकता का उपयोग किया जा रहा है। पूर्व में जहां कोदो, कुटकी और कुल्थी जैसी निकृष्ट फसलें ली जाती थी वहीं अब नमी उपचार कर चना, उड़द, गेहूं, धान, कपास और सोयाबीन तक लिया जा रहा है। रबी फसलों के क्षेत्र में विस्तार हुआ है। ग्रामीणजनों द्वारा अपने खेतों में मेढ़ का निर्माण हदबंदी कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है। इन मेढ़ों पर भी कृषकों को मूंग, उड़द, घास, रतनजोत या कम छाया वाले फलदार वृक्षों के लिए उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सुदूर आदिवासी अंचल में कृषकों द्वारा कृषि वानिकी, सिल्वी पाश्चर का उपयोग आरंभ करना हरितक्रांति की दस्तक है।

Green Revolution

Motivation and awareness created in watershed development campaign is being used, to bring in better adoption of new and scientific agricultural techniques in the disthict. The cultivation of Kodo, Kutki and Kulthi has been completely replaced by good quality high yielding crops of gram, Urad, Wheat, Paddy, cotton and Soyabean due to the moisture conservation measures. An increase in the area under Rabi crop has been achieved. All the villagers have voluntarily taken up farm ponds on their farms. Farmers are encouraged to take up Moong, Urad, Grass, Ratanjot, Bamboo or fruit bearing trees on their field bunds. The adoption of agro-forestry, silvipasture and dryland horticulture by farmers in this remote tribal belt could be adjudged as a firm first step towards green revolution.

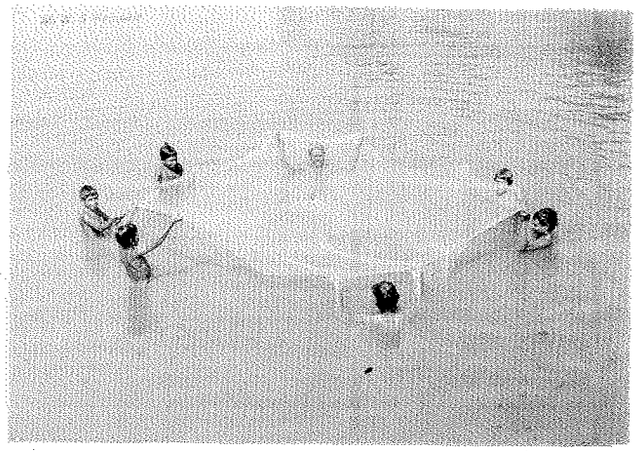

श्वेतक्रान्ति

चारे की उपलब्धता हो जाने एवं बायोगैस संयंत्र निर्मित हो जाने और साथ ही पशुओं द्वारा अनियंत्रित चराई की रोकथाम होने से दुधारू पशुओं के पालन के लिए आधार तैयार हो गये हैं। आयआरडीपी योजना में अब केवल जलग्रहण ग्रामों तथा मिल्करूट पर पड़ने वाले ग्रामों में ही दुधारू पशुओं को उपलब्ध कराया जा रहा है एवं पूर्व के निम्न श्रेणी के पशुओं के उत्थान के लिए कृत्रिम गर्भाधान को स्वयं सेवी संस्थाओं ('मुख्यतः' 'बैफ' एवं 'इरकान') के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। गांव में उपलब्ध छोटे-छोटे तालाबों में मछली पालन के लिए समितियाँ निर्मित कर मछली के बीजों एवं मछली पालन की समस्त जानकारी भी समितियों को उपलब्ध करायी जा रही है। ऐसे मत्स्योत्पादन पर मछुआरों के स्वयं सहायता समूह को पट्टा देकर संपूर्ण अधिकार सौंपे गए है।

White revolution

A ground for dairy development has been prepared due to availability of fodder, construction of biogas plants and control of grazing. Milch cattle are provided under IRDP scheme only in watershed villages and villages on milk-routes. Low yield variety milch cattles are improved by artificial insemination, done by non-governmental organisations, BAIF and IRCON. Small tanks available in the villages are taken up for fisheries development by creating fisheries co-operative societies and providing these societies with all the necessary inputs. Fisherman self-helpfgroups are given rights over all such fisheries units.

शुष्क जलवायु में फलों का उत्पादन

जलग्रहण क्षेत्रों में देशी प्रजातियों के बेर के पौधों को बंडिग के माध्यम से उन्नत किया गया है। इस प्रकार ट्रायसेम योजना में प्रशिक्षित स्वयं सेवकों द्वारा लगभग २.०० लाख पौधों को उपचार किया गया है। इस कार्यवाही से प्रतिवर्ष ५०० किग्रा प्रति वृक्ष बेर की पैदावार में बढ़ौत्री हो जाना संभावित है। कल्पतरू योजना में निजी खेतों पर शुष्क उद्यानिकी एवं कृषि उद्यानिकी के रूप में बेर एवं आंवला वृक्षों का ४१६ हेक्टर में कार्यक्रम सु रो यो में प्रारंभ कराया गया है। अगले वर्षो में आंवला का प्रसार एवं उत्पादन कई गुना किये जाने का प्रस्ताव है।

Dryland Horticulture.

Indigenous varieties of Ber have been improved into high yielding variety by budding/ grafting in watershed areas. Around 2.00 lakh indigenous Ber plants have been grafted in this manner by volunteers previously trained under TRYSEM scheme. This programme is expected to increase the yield by 500 Kg. per plants annualy. Dryland horticulture and agro-horticulture of Ber and Amla in 416 hects. on private farms has been taken up in Kalptaru scheme of Employment Assurance Scheme. Manyfold increase in extension and production of Amla in Next few years has been proposed.

आदिवासियों ने अपनायी कुल्हाड़बंदी

ग्राम वन समितियों के माध्यम से ग्रामीणजनों को वनों के विनाश को रोकने के लिए रणनीति बनाकर कुल्हाड़बंदी के लिए प्रेरित किया गया। जिले में हजारों ग्रामीणजनों द्वारा अपनी कुल्हाड़ियाँ वन समिति को स्वेच्छा से सौंप दी गई। कुल्हाडी आदिवासी का परंपरागत औजार है। वनों के विन्नाश को रोकने और फिर से पर्यावरणीय संतुलन कायम करन्ने के लिए उनके द्वारा अपनी कुल्हाड़ी का त्याग किये जाने की घटना को एतिहासिक घटना के रूप में निरूपित किया जा सकता है। इसी प्रकार ग्राम वन समितियों एवं जलग्रहण विकास समितियों के द्वारा चराई बंदी का अभियान बढ़े पैम्माने पर लिया गया है। जलग्रहण क्षेत्र में जानवरों को खूटे पर ही चारा देने की प्रथा का विस्तार किया जा रहा है।

Tribals Adopt Kulhad Bandi

Villagers have been motivated to adopt 'Kulahad Bandi' (surrender of axes) to stop destruction and further degradation of fore sts by the medium of village forest protection committees. Thousands of villagers in the district have voluntarily deposited their axes to forest committees and forest department. Axe, is a traditional tool of tribals. This campaign of surrendering their axes in order to curb the destruction of forests and bring back the ecological balance can be adjudged as a historical event in the history of Jhabua. A campaign has been launched for stopping uncontrolled grazing in the villages through village forest committees and watershed development committees. Stall feeding of cattle is being promoted in the villages.

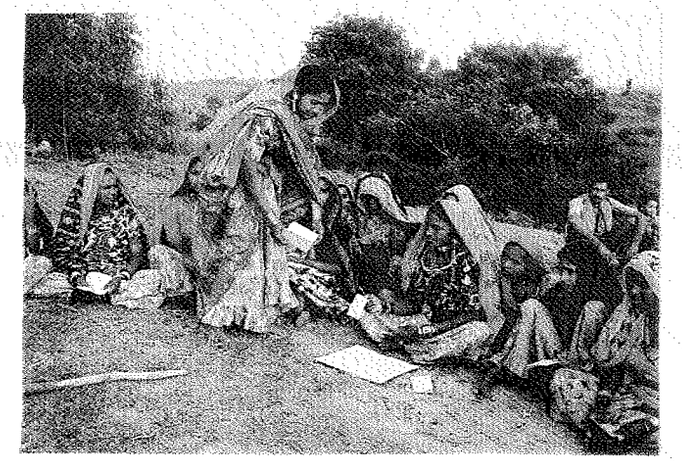

''बयरा नी कुलड़ी (महिलाओं का अपना बैंक)

१५ से २० महिलाओं का समूह प्रतिदिवस बैठक कर ग्राम में ही प्रति महिला एक रूपया एकत्र करती है। तीन से लेकर ६ माह तक उक्त गतिविधि उपरान्त डवाकरा योजना से उन्हें सहायता उपलब्ध करायी जाती है। इस राशि का उपयोग उनके द्वारा सस्ते ब्याज पर ग्राम के लोगों को विभिन्न कार्यों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। जिले में ऐसे ३५८ बयरानी कुलड़ी विद्यमान है। इससे ऋणग्रस्त झाबुआ के आदिवासी समाज को बेरोजगारी एवं शोषण के चंगुल से बचाया जा रहा है। साथ ही महिलाओं में आत्मविश्वास की एक नयी जागृति भी उत्पन्न की गयी है। इन बयरानी कुलड़ियों, को उत्पादक गतिविधियों में लगाया जा रहा है जिनमें मुख्यत: महिला उद्योग, सब्जी उत्पादन, मछली पालन, गलसन एवं अन्य ग्रामोद्योग प्रमुख है।

Baira ni Kuladi - Women's Bank

A group of 15 to 20 women meet everyday in the village and collect a rupee each. After 3 to 6 months, assistance under DWCRA scheme is given to them. This revolving fund is used by the group to provide loans on easy interest rates for productive or non productive activities. Presently, there are 358 such Baira-ni-Kuldis in existence in the district. This has resulted in saving the indebted tribals from the clutches of exploitation. A new consciousness towards empowerment of women has been percieved in the dist. These women banks are entering into the arena of productive activities comprising mainly of village industries, vegetable production, fisheries, beadwork and allied activities.

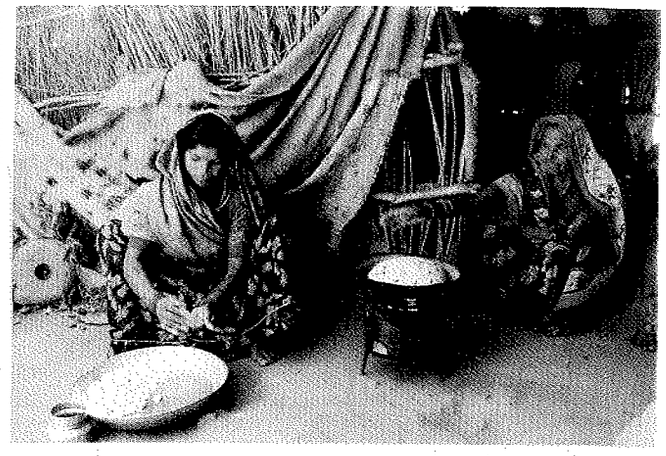

गैर परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों का प्रसार

जिले में जंगलों के विनाश से जलाऊ लकड़ी तक लाने के लिए महिलाओं को कई किमी की कष्टदायी पदयात्रा करना पड़ती थी। ६२ रुपये प्रति सिगड़ी की दर पर ग्रामीणजनों को ५००० धुंआ रहित सिगड़ियाँ उपलब्ध करायी जा चुकी है। इन सिगड़ियों का उपयोग ग्राम की महिलाएं अत्यधिक चाव से करती है क्योंकि इनसे न सिर्फ ४० प्रतिशत ईधन की कम खपत होती है वरन कम धुंआ होने से आंखों की जलन से भी निजात मिलती है। इसी प्रकार ५०० सोलर कुकर भी ग्रामीणजनों ने जल संरक्षण क्षेत्रों में अपनाये है। अधिक मवेशी वाले ग्रामों में चारे की उपलब्धता को देखते हुए बायोगैस की स्थापना करायी गई है। इन संयंत्रों के संचालन से ग्राम्मीण जनों को जैविक खाद और ईधन उपलब्ध हो रहा है।

Propogation of non-conventional sources of energy :

Due to degradation of forests women are forced to travel long distances to bring fuel wood. 5000 smokeless Sigris have already been distributed at the rate of Rs. 62/- a piece. These Sigris are very popular among women in these villages because these save 40% fuelwood and also save their eyes from the ill-effects of smoke. Similarly 500 solar cookers are being used by villagers in watershed areas. Biogas plants have been constructed in villages keeping cattleheads and availability of fodder in consideration. The functioning of these biogas plants has enhanced the availability of biofertilizers and fuelwood.

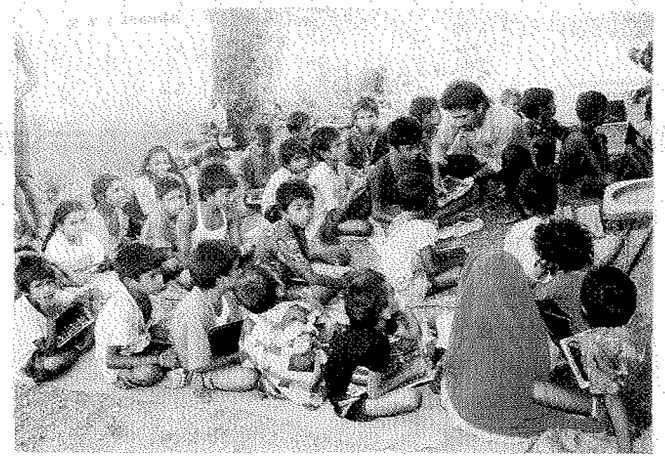

गांव वाले चलाते हैं खुद के स्कूल / आंगनवाड़ी

सरकार द्वारा शालाओं और आंगनवाड़ियों के संचालन की अपनी सीमा है, अत: ग्रामीण जनों द्वारा जलग्रहण क्षेत्रों में स्वप्रेरणा से फलियों (मजरे/पारे) में प्रत्येक परिवार से ५/- रुपये प्रतिमाह एकत्र कर फलिया स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। इनसे शिक्षा के लोक व्यापीकरण को नयी दिशा मिली है। इसी प्रकार साक्षरता अभियान में प्रौढ़ शिक्षा एवं प्रायोगिक शिक्षा का भी प्रसार किया जा रहा है। ग्रामीणजनों द्वारा ही गांव के छोटे बच्चों तथा गर्भवती माताओं के लिए पोषण आहार एवं अन्य कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए स्वयं के व्यय से पोरियावाड़ी (उपआंगनवाड़ी) का संचालन किया जा रहा है। मुख्यत: महिलाओं द्वारा जलसंग्रहण क्षेत्रों में साक्षरता कक्षाओं एवं पोरियावाड़ी के संचालक का कार्य सम्पादित कराया जा रहा है।

The villagers manage their own institutions

Due to limitations of government in running schools and Anganwadis in all hamlets, villagers have voluntarily taken up management of Falia schools by collecting rupees 5/- per family every month as a community contribution. This has given a new direction to universalization of education in the district. Adult education has been promoted through literacy campaign. Villagers have also taken up management of Poriawadi (Sub-Anganwadi) through their voluntary contribution to cater to nutritional and other needs of children and pregnant mothers. The literacy classes and Poriawadis are managed prinarily by the women of the watershed villages.

शराबबंदी एवं नसबंदी की दिशा में

परंपरागत रूप से झाबुआ जिले में आदिवासी समाज शराबखोरी की बुरी आदत से ग्रस्त रहे हैं। शराब को छुड़वाने के लिए विशेषत: महिलाओं के माध्यम से जनजागरण आरंभ कराया गया है। जलग्रहण क्षेत्रों में मोद, रूपारेल, भावड़ापाडा आदि गोमा में शराब का उपयोग समाज की अभिप्रेरणा से पूर्णत: बंद हो गया है । अन्य जलग्रहण क्षेत्रों में भी शराब बंदी के कार्य को मुख्य आधार बनाया गया है। इसी प्रकार प्राकृतिक संसाधनों पर जनसंख्या विस्फोट से बहुत अधिक भार बढ़ चुका है। इसको रोकने के लिए पर्यावरण कार्यक्रमों को ग्रामों तक पहुंचाया गया है। नसबंदी शिविरों के साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से ग्रामीणजनों को गर्भ निरोधक भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

Towards Planned Family and Prohibition

Traditionally for the tribal society the consumption of liquor is their way of life. Awareness specially through women is created for prohibition. Consumption of liquor has been totally prohibited in wathershed villages like Mod, Ruparel, Bhavadapada etc. In other watershed areas prohibition is taken up on priority. Population explosion has caused enormous pressures on natural resources. Environmental improvement programmes have been taken up to the villagers to balance the natural forces. Contraceptive methods are made available to the villagers in family planning camps and condoms are being distributed through Public Distribution System.

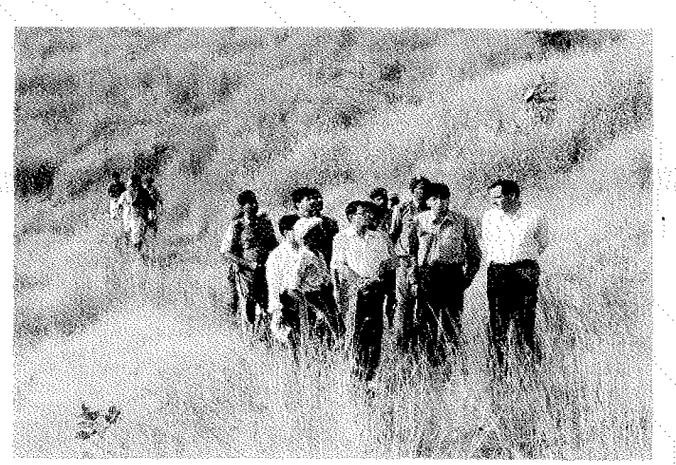

परीक्षा एवं परिणाम

जिले में जलग्रहण कार्यो का अवलोकन करने हेतु विगत एक वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री श्री दिग्विजयसिंहजी, मान. आ.जा.क. मंत्री श्री कांतिलालजी भुरिया, मान. सह. मंत्री, श्री बापूसिंहजी डामोर, मान. सांसद श्री दिलीपसिंहजी भूरिया, वन महानिरीक्षक, भारत सरकार श्री एहमदी, प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास म.प्र. शासन श्री अरूण गुप्ता, सचिव, ग्रामीण विकास म.प्र. शासन श्री आर. परशुराम, संचालक, राजीव गांधी मिशन श्री एन. बैजेंद्र कुमार आदि के द्वारा सघन भ्रमण किये गये और झाबुआ जिले के कार्यो की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई । जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय श्री जामसिंहजी अमलियार के द्वारा कार्यक्रम को सही दिशा हर पल दी जाती रही है ।

Appreciation

In last one year Hon'ble Chief Minister Shri Digvijay Singhji, Hon'ble Minister for Tribal welfare Shri Kantilal Bhuria, Hon'ble Co-operative Minister Shri Bapoosinghji Damor, Hon'ble Member of Parliament Shri Dilip Singhji Bhuria, Inspector General Forests, Government of India, Shri Ahmadi, Principal Secretary, Rural Development Govt. of M.P., Shri Arun Gupta, Secretary, Rural Development Govt. of M.P. Shri R. Parshuram, Director, Rajiv Gandhi Mission on Watershed Development, Shri N. Baijendra Kumar have visited the district and appreciated the Integrated Watershed Development Programme. Zila Panchayat President Hon'ble Shri Jamsinghji Amliyar has always given direction to this programme.